(b) whether they have submitted their report;

(c) if so, the broad details thereof;

(d) whether they have also demanded that the aid provided so far is not sufficient in view of the grave situation created in the State due to this drought;

(e) if so, how much further aid has been recommended; and

(f) to what extent the Union Government has agreed to provide aid including foodgrains?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): (a) No Sir. The State Government was requested to send a fresh Memorandum for the second visit of the Central Team. The reply from the State Government is awaited.

(b) and (c): Do not arise.

(d) No report from the State Government has been received regarding the adequacy or otherwise of the ceiling of expenditure sanctioned for Central assistance for drought relief in Karnataka.

(e) and (f): Do not arise.

राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वयन

698. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) मंत्रालय में और इसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं और प्रत्येक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या, पदों और उनके वेतनमानों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि राजभाषा समिति की उप-समिति ने मन्त्रालय, इसके विभागों और भारतीय खाद्य निगम जैसे कार्यालयों का निरीक्षण किया था और वहां हिन्दी अनुभागों तथा हिन्दी प्रकाशनों के प्रति दिखाई जा रही उदासीनता समाप्त करने की सलाह दी थी ; और

(ग) उक्त समिति की सिफारिशों के बाद भी भारतीय खाद्य निगम में हिन्दी प्रकाशनों को अंग्रेजी प्रकाशनों के बराबर दर्जा और सुविधाएं न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मन्त्रालय तथा इसके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों में की गई व्यवस्था में निम्नलिखित शामिल हैं :--

(1) अनुवाद और अन्य महत्वपूर्ण काम को हिन्दी में करने के लिए स्टाफ की मंजूरी ;

(2) हिन्दी प्रशिक्षण, आशुलिपि, टाइप आदि में विभिन्न अनुभागों के स्टाफ का प्रशिक्षण ;

(3) स्टाफ को अपेक्षित सहायक साहित्य उपलब्ध कराना जिससे कि हिन्दी में काम करने में सहूलियत हो ;

(4) पर्याप्त संख्या में हिन्दी टाइपराइटरों की व्यवस्था करना ;

(5) मन्त्रालय में निदेशक (राजभाषा) द्वारा निरीक्षण करना और हिन्दी में किए गए काम की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करना ; और

(6) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें करना) ।

हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, पदों के ब्यौरे तथा वेतनमान के सम्बंध में अनुबंध 1 के रूप में एक विवरण सभा पटल पर रखा है । [ग्रन्थालय में रखा गया । दीखिये संख्या एल. टी.--2209/81] ।

(ख) संसदीय राजभाषा समिति की उप-समिति ने मन्त्रालय के विभागों और कुछ कार्यालयों का निरीक्षण किया था। किन्तु यह कहना सही नहीं है कि समिति ने वहां के हिन्दी अनुभागों और हिन्दी प्रकाशनों के प्रति उदासीनता का रुख अपनाने के बारे में कोई शिकायत की है।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

Assistance of Chiroli Irrigation Project

*699. DR. KRUPASINDHU BHOI: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal from the Government of Orissa for giving Central assistance for the Chiroli Irrigation Project in the district of Sambalpur;

(b) if so the details thereof; and

(c) the amount earmarked for the project in the Sixth Five Year Plan?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): (a) to (c) No proposal for Central assistance for Chiroli Project has been received from the Orissa State Government.

The report on Chiroli Irrigation Project has also not been received so far in the Central Water Commission from Orissa Government. According to the information contained in the Sixth Plan document of Orissa State, the project is estimated to cost Rs. 30 crores and will create an irrigation potential of 42000 ha. The amount to be provided in the Sixth Plan for this project will depend on the clearance of the project and availability of funds with the State Government.

New Telephone Connections

*700. SHRI KRISHNA PRATAP SINGH: Wil lthe Minister of COMMUNICATIONS be pleased to lay a statement showing:

(a) the salient features of programme for the expansion of various telephone exchanges and when the expansion programme is likely to be completed in respect of each of the telephone exchanges in Delhi;

(b) the total number of persons in the waiting list for new telephone connections in various categories in each of the Telephone Exchanges in Delhi; and

(c) when the telephone connections are likely to be provided in the Jan Path Exchange and other exchanges where less than 1000 persons are on the waiting list as on the 31st December, 1980?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI C. M. STEPHEN): (a) Part 'A' of statement laid on the Table of the House summaries the main programme of expansion of telephone exchanges tentatively planned to be completed during 1981-82 and 1982-83.

(b) Part 'B' of the statement shows the number of persons in the waiting list in areas served by different exchanges in Delhi as on 1-3-81.

(c) It is anticipated that in general most of the applicants on the waiting lists for new telephone connections in Delhi as on 1-3-81 including those in Janpath and other exchanges with waiting lists of less than 1000 will be provided telephone connections progressively by 1985.